

भारतीय कृषि किस प्रकार खाद्य के अभाव से खाद्य-अतिरेक स्तर तक रूपान्तरित हुई है ? भारतीय कृषि के विविधीकरण हेतु की गई विभिन्न सरकारी नीतियों का वर्णन कीजिए । (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) [UPSC 2026]

How Indian agriculture has been transformed from food scarcity to food surplus level? Explain the various government policies implemented for diversification of Indian agriculture. 15 (Answer in 250 words)

<u>भारतीय कृषि-खाद्य-अभाव से अतिरेक एवं विविधीकरण: संक्षिप्त रूपरेखा</u> <u>टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?</u> भारत की खाद्य सुरक्षा, कृषि संधारणीयता तथा किसानों की आय बढ़ाने हेतु खाद्यान्न उत्पादन से फसल विविधीकरण की दिशा में नीतिगत बदलाव को समझना आवश्यक है । <u>प्रश्न के कीवर्ड्स</u> ✓ खाद्य-अभाव से खाद्य-अतिरेक ✓ हरित क्रांति एवं तकनीकी नवाचार ✓ कृषि विविधीकरण ✓ उच्च मूल्य वाली फसलें व संबद्ध क्षेत्र <u>प्रस्तावना</u> 1960 के दशक की हरित क्रांति और संस्थागत सुधारों के बल पर भारत खाद्यान्न-अभाव से उबरकर खाद्य-अतिरेक एवं निर्यातक राष्ट्र बना । <u>मुख्य भाग</u> 1. खाद्य-अतिरेक तक रूपांतरण के मुख्य घटक	✓ तकनीकी क्रांति (हरित क्रांति) ✓ मूल्य समर्थन व संस्थागत ढांचा ✓ सिंचाई व साख विस्तार 2. कृषि विविधीकरण हेतु सरकारी नीतियां ✓ बागवानी क्षेत्र ✓ पशुपालन व डेयरी ✓ मत्स्य पालन (नीली क्रांति) ✓ तिलहन एवं दलहन ✓ जैविक व प्राकृतिक खेती ✓ खाद्य प्रसंस्करण <u>आगे की राह</u> ✓ जलवायु-अनुकूल कृषि ✓ विपणन सुधार ✓ फसल प्रोत्साहन <u>निष्कर्ष</u> भारतीय कृषि को केवल 'खाद्य-सुरक्षा' तक सीमित न रखकर 'पोषण-सुरक्षा', 'कृषक आय वृद्धि' और 'पर्यावरणीय निरंतरता' की दिशा में ले जाना अनिवार्य है, ताकि भारत 2027 तक 'वैश्विक कृषि-खाद्य केंद्र' बन सके ।
---	--

स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि भयंकर खाद्यान्न संकट से जूझ रही थी, लेकिन 1960 के दशक की हरित क्रांति और तकनीकी नवाचारों के बल पर भारत खाद्यान्न-अभाव की स्थिति से उबरकर **खाद्य-अतिरेक एवं शुद्ध निर्यातक राष्ट्र** के रूप में रूपांतरित हुआ है। वर्तमान में, भारतीय कृषि अपनी खाद्य सुरक्षा को संधारणीय बनाने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से पारंपरिक खाद्यान्न फसलों से आगे बढ़कर फसल **विविधीकरण** की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है।

खाद्य-अभाव से खाद्य-अतिरेक तक रूपांतरण के मुख्य घटक

1. **तकनीकी क्रांति (हरित क्रांति):** 1960 के दशक में उच्च उपज वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई तकनीक के समन्वित प्रयोग ने खाद्यान्न उत्पादकता को अभूतपूर्व गति दी।

उदा: गेहूं में 'कल्याण सोना' व 'सोनालिका' तथा चावल में 'IR-8' किस्मों के प्रयोग से पंजाब और हरियाणा में खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई।

2. **मूल्य समर्थन और संस्थागत ढांचा:** न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा बफर स्टॉक के निर्माण ने किसानों को बाजार जोखिम से सुरक्षा दी।

उदा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु FCI प्रतिवर्ष लाखों टन गेहूं और चावल का बफर स्टॉक बनाए रखता है।

3. **सिंचाई एवं बुनियादी ढांचे का विस्तार:** बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं और ट्यूबवेल तकनीक ने सिंचित कृषि क्षेत्र का दायरा बढ़ाया।

उदा: इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने राजस्थान के शुष्क इलाकों को खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्रों में बदल दिया।

4. **संस्थागत साख और यांत्रिकीकरण:** किसान क्रेडिट कार्ड और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण (PSL) ने किसानों की पूंजी तक पहुंच सुलभ बनाई।

उदा: किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को रियायती दरों पर अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

भारतीय कृषि के विविधीकरण हेतु सरकारी नीतियां



पारंपरिक गेहूं-धान चक्र से हटकर उच्च मूल्य वाली फसलों, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित नीतियां लागू की गई हैं:

1. **बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहन:** मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फल, सब्जी और मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देता है।

उदा: 'ऑपरेशन ग्रीन्स' (टॉप टू टोटल) के तहत टमाटर, प्याज और आलू की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला हेतु कोल्ड-स्टोरेज और क्लस्टर विकास किया जा रहा है।

2. **पशुपालन एवं दुग्ध विकास:** पशुपालन अवसंरचना विकास निधि डेयरी प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा देती है।

उदा: भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, जिसमें अमूल जैसे सहकारी मॉडल और राष्ट्रीय गोकुल मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है।

3. **मत्स्य पालन एवं नीली क्रांति:** प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तटीय एवं अंतर्देशीय मत्स्य पालन, गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज और अवसंरचना विकास पर केंद्रित है।

उदा: आंध्र प्रदेश और गुजरात में आधुनिक झींगा कृषि के विस्तार से भारत का समुद्री उत्पाद निर्यात 60,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

4. **तिलहन एवं दलहन विविधीकरण:** राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-पाम ऑयल खाद्य तेलों में आयात निर्भरता कम करने के लिए पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उदा: पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में ऑयल पाम के तहत नए क्षेत्रों को आच्छादित किया जा रहा है।

5. **जैविक एवं प्राकृतिक खेती:** परंपरागत कृषि विकास योजना क्लस्टर आधारित जैविक खेती और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण को प्रोत्साहित करती है।

उदा: सिक्किम को विश्व का पहला 100% पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया है, तथा गंगा किनारे 'नमामि गंगे' परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं।

6. **खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन:** प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कटाई-पश्चात नुकसान को रोकने और कृषि-उत्पाद का मूल्यवर्धन करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करती है।

उदा: आंध्र प्रदेश, असम और पंजाब जैसे राज्यों में 'मेगा फूड पार्क' की स्थापना कर कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाया जा रहा है।

आगे की राह



1. **जलवायु-अनुकूल कृषि:** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्मार्ट/सूखा-रोधी बीजों का उपयोग तथा 'प्रति बूंद अधिक फसल' (सूक्ष्म सिंचाई) से जल संकट का समाधान।

2. **विपणन एवं अवसंरचना:** राष्ट्रीय कृषि बाजार ('एक राष्ट्र, एक बाजार') का सुदृढ़ीकरण और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना तथा कृषि अवसंरचना कोष (शीत-श्रृंखला/खाद्य पार्क) से कटाई-पश्चात नुकसान को कम करना
3. **फसल विविधीकरण:** श्री अन्न, दलहन-तिलहन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का पुनर्संतुलन तथा धान की खेती छोड़ने पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन।
4. **डिजिटल कृषि एवं किसान संगठन:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) व ड्रोन आधारित 'डिजिटल कृषि मिशन' और 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन से छोटे किसानों की बाजार में सौदेबाजी क्षमता बढ़ाना।
5. **संबद्ध क्षेत्रों का विकास:** पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) के विकास से ग्रामीण आय में विविधता व स्थिरता लाना।



निष्कर्षतः भारतीय कृषि को 'खाद्य-सुरक्षा' से आगे बढ़ाकर 'पोषण-सुरक्षा', 'कृषक आय संवर्धन' और 'पर्यावरणीय निरंतरता' की ओर ले जाना अनिवार्य है। इन सुदृढ़ नीतिगत कदमों से भारत 2027 तक वैश्विक कृषि-खाद्य केंद्र बन सकता है।

JOIN US-RESULT MITRA

